tary does not fall within the purview of this question. Sir, for that the hon. Member can give us a separate notice..

श्री राम भगत पासवान : मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि आई०टी०सी० कम्पनी जो है वह किस किस देश को सिगरेट सप्लाई कर रहा है ?

श्री उपसभापति : यह सवाल कहां से इसमें उठता है। सिगरेट सप्लाई का सवाल नहीं उठता है।

श्री राम भगत पासवान : नेपाल के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें नेपाल जो है उसने हमारे यहां से करीब 9112 टन टोबेको की मांग की थी चाईना ने भी इसी तरह से करीब 21,740 टन की मांग की थी। नेपाल जो है वह फ्री ट्रेड कंट्री है। इसलिए वे जो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे साझीदार हो जायेंगे तो नेपाल से ही फारेन सप्लाई होना शुरू हो जायेगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि भारत का राजस्व बचे, जो यहां के टोबेको प्रोड्यूसर्स हैं उन पर इफेक्ट नहीं पड़े, उनको फायदा मिलता रहे, इसलिए उनका जो प्रोपोजल है क्या सरकार उसको रिजेक्ट कर देने की कृपा करेगी ?

श्री राम दुलारी सिन्हा : मैंने पहले ही प्रारम्भिक जवाब में बताया था कि जाइंट वेन्चर के रूप में वहां पर सिगरेट फैक्ट्री खोलने के लिए इस कम्पनी ने सरकार को आवेदन किया था। इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी में जो बातचीत हुई और आई०टी०सी० के प्रोपोजल के मुताबिक ही इसे डेफर्ड कर दिया गया और अदर पार्ट्स पूरक प्रश्न के हैं वे इसके परव्यू के अंदर नहीं आते हैं। उसके लिए दूसरा सवाल अगर करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगी।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संयुक्त उपक्रम के मुख्य मुद्दे क्या हैं, इस जवाइंट वेन्चर के सैलियंट फीचर्स क्या हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : इसका मुख्य मुद्दा तो था कि equity share was proposed.

I have already explained the salient features of the proposed ventures, however some more details are as under:-

Entitlement to ITC from this joint venture are projected as: Technical services for the first 3 years in Nepalese currency 16.5 lakhs per annum, next 3 years N.C. at 8.25 lakhs per annum, and next 3 years-N.C. 4.1 lakhs per annum. Royalty: first three years-NC. 8 lakh per annum, next 3 years it is NC 4 lakhs per annum and next 3 years again, it is N.C. 2 lakhs per annum. Turn Key services-preparations for feasibility study: NC 3 lakh and turn-key fee NC. 5 lakh for the first year from the date of signing of the agreement and N.C. 21 akhs for the second year.

WELCOME TO THE VISITING MEMBERS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF MAURITIUS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have a very pleasant announcement to make. We have with us this morning a delegation of Members of the Legislative Assembly of Mauritius led by Hon'ble Shri Chattradhari Daby, speaker of the Legislative Assembly, Mauritius. The delegation is on a visit to India from the 15th to 23rd November, 1983. The Members of the delegation are now seated in the Special Box. On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a very hearty welcome to the Leader and other Members of the delegation and wish our distinguished guests a very enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that by the time they leave us, they would have seen and learnt more about our country and our people. Through them we convey our greetings and best wishes to the Legislative Assembly of Mauritius and

the friendly people of the Republic of Mauritius. I have no doubt that this visit of the Parliamentary delegation will further strengthen the traditional and friendly ties that exist between our two countries.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन् आई० टी० सी० के बारे में सरकार कह रही है, यानी कि मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में यह कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है तो मैं यह जानता हूं कि 22 अगस्त को मैंने स्पेशल मैंशन के द्वारा सवाल पूछा था, तो सरकार की तरफ से जो हमको जवाब दिया गया है, वह मैं थोड़ा सा कोट कर देना चाहता हूं :

"इस इंडियन टोबेको कम्पनी पर 108 करोड़ के ऊपर बकाया है, और यह चल करके फिर आगे कहते हैं कि यह 108 करोड़ से बढ़ कर 117 करोड़ 87 लाख रुपया हो गया है ।"

यह कम्पनी, श्रीमन् आप आश्चर्य करेंगे कि इस कम्पनी के 31 जुलाई 1983 को मौर्य होटल में, जो इनका कन्सर्न है, उस पर एक छापा पड़ा और उस छापे में चरस तथा और भी आपत्तिजनक तस्करों का सामान प्राप्त हुआ। यह सारे डाकुमेंट्स हमारे पास हैं और गवर्नमेंट की सभी चिट्ठियां हमारे पास हैं चिट्ठियां मैं मंत्री महोदया को दिखा रहा हूं यह चिट्ठियां हमको प्रणब बाबू ने लिखा हैं, उसके जवाब में हमें लिखी हैं।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कम्पनी जो तस्करी के कार्य में देश में लगी हो और जिनके ऊपर 117 करोड़ रुपया बकाया पड़ा हो और जब उनके ऊपर रेड हुआ, छापा पड़ा और छापे के दौरान जब यह सारा सील हो गया, तो वे लोग हाई कोर्ट में चले गये और आज तक वह मामला हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो ऐसी कम्पनी को जो देश में तस्करी का काम करती हो, देश की वित्तीय व्यवस्था को खराब करती हो, उस कम्पनी को विदेश के साथ धंधा करने की इजाजत देने के ऊपर क्यों विचार किया जा रहा है, कैसे आपने विचार किया, कैसे इस पर आपने सोचा ? और अभी भी आप कह रहे हैं कि इस पर विचार करने के लिए हमने दे दिया है आप यह क्यों कह रहे हैं ?

आप सदन को और मुल्क को आश्वासन दीजिए कि ऐसी तस्करी करने वाली कम्पनी को हम कहीं भी बाहर पैसा लगाने की इजाजत नहीं देंगे, नहीं तो यह यहां तस्करी करेंगे और माल वहां तैयार करेंगे । मैं राम भगत पासवान जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यह सवाल पूछा है कि यहां से जो माल देश के बाहर जाता है, जो यहां से एक्सपोर्ट होता है वह नेपाल से एक्सपोर्ट होगा, जो हमारा दोस्त देश है। सारा धंधा वहां से होगा ऐसी कम्पनियों को छूट देने पर क्यों विचार किया जा रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, जोइन्ट वेंचर्स का एक प्रमुख लक्ष्य होता है कि हमारे जो केपिटल गुड्स हैं उन का एक्सपोर्ट हो, हमारे नो-हाउ का एक्सपोर्ट हो और इस संयुक्त इन्वेस्टमेंट से हमें रायल्टी भी मिले। तो जहां तक निर्णय की बात है, अभी तक कोई निर्णय सरकार ने लिया नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारी केपिटल गुड्स का कितना एक्सपोर्ट होगा, हम को रायल्टी कितना मिलेगी—राज्य मंत्री जी ने बताया कि इतना हर साल हमको मिलेगा और हमारा नो-हाउ कितना एक्सपोर्ट होगा साथ ही साथ अगर हमारी टोबेको